MODEL ANSWER

Q. Analyze the current state of public funding for higher education in India, with a focus on disparities among states and their spending patterns.

Higher education plays a crucial role in India's socio-economic development by fostering innovation, skill development, and employment generation. However, disparities in public funding across states have led to uneven growth in the sector. While some states allocate a significant portion of their budget to higher education, others lag due to financial constraints and policy priorities.

Current Public Expenditure on Higher Education

- **Overall Spending**: Public expenditure on social services, including education, stands at 7.8% of GDP (2023-24).
- **State-wise Allocation:** Maharashtra leads with ₹11,421 crore, followed by Bihar (₹9,666 crore) and Tamil Nadu (₹7,237 crore), whereas smaller states like Sikkim (₹142 crore) and Nagaland (₹167 crore) have the lowest allocations.
- **Higher Education vs. GSDP:** States like Bihar (1.56%) and Jammu & Kashmir (1.53%) allocate a higher share, while Telangana (0.18%) and Gujarat (0.23%) allocate the least.

Disparities in Spending Patterns

1. **Regional Disparities:**
    - Higher university density in **Sikkim (10.3 per lakh population)**, while **Bihar (0.2)** and **Uttar Pradesh** fall below the national average.
    - **Kerala's literacy rate of 94%** contrasts with **Bihar's 70%**, indicating uneven investment outcomes.
2. **Focus on Targeted Welfare:**
    - Increased funding in schemes like **Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)** aims to improve infrastructure.
    - **NEP 2020** emphasizes greater budgetary support, but rural-urban education gaps persist.
3. **Challenges in Public Funding:**
    - **Inadequate Infrastructure:** Rural institutions lack faculty and research facilities.
    - **Inequitable Access:** Marginalized groups still face barriers despite rising scholarships.
    - **Underutilization of Funds:** Delayed implementation reduces the impact of allocated budgets.

To bridge disparities in higher education funding, states must ensure a minimum allocation of 6% of GDP for education, as recommended by NEP 2020. Expanding public-private partnerships (PPP) can attract investments, enhancing infrastructure and research capabilities. Strengthening governance and accountability is crucial to minimizing fund leakages and ensuring effective utilization of allocated budgets. Additionally, promoting inclusive digital learning through improved e-learning infrastructure can help bridge the digital divide, especially in underprivileged regions. A well-balanced funding strategy will not only ensure equitable access and quality education but also contribute to long-term national development by fostering a skilled and knowledgeable workforce.

Samyak
An Institute For Civil Services

प्रश्न. राज्यों के बीच वित्तीय असमानताओं और उनके व्यय पैटर्न पर विशेष ध्यान देते हुए, भारत में उच्च शिक्षा के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करें।

उच्च शिक्षा नवाचार, कौशल विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देकर भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालाँकि, राज्यों में सार्वजनिक वित्त पोषण में असमानताओं के कारण इस क्षेत्र का विकास असमान रहा है। जहाँ कुछ राज्य अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा उच्च शिक्षा के लिए आवंटित करते हैं, वहीं अन्य वित्तीय बाधाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं के कारण पिछड़ जाते हैं।

उच्च शिक्षा पर वर्तमान सार्वजनिक व्यय

- **समग्र व्यय:** शिक्षा सहित सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद (2023-24) का 7.8% है।
- **राज्यवार आवंटन:** महाराष्ट्र ₹11,421 करोड़ के साथ सबसे आगे है, उसके बाद बिहार (₹9,666 करोड़) और तमिलनाडु (₹7,237 करोड़) हैं, जबकि सिक्किम (₹142 करोड़) और नागालैंड (₹167 करोड़) जैसे छोटे राज्यों में सबसे कम आवंटन देखा गया है।
- **उच्च शिक्षा बनाम जीएसडीपी:** बिहार (1.56%) और जम्मू और कश्मीर (1.53%) जैसे राज्य जीएसडीपी का उच्च हिस्सा आवंटित करते हैं, जबकि तेलंगाना (0.18%) और गुजरात (0.23%) सबसे कम आवंटित करते हैं।

खर्च के पैटर्न में असमानताएँ

1. **क्षेत्रीय असमानताएँ:**
    1. सिक्किम में विश्वविद्यालय घनत्व अधिक है (प्रति लाख जनसंख्या पर 10.3), जबकि बिहार (0.2) और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय औसत से भी नीचे हैं।
    2. केरल की साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार की साक्षरता दर 70% है, जो असमान निवेश परिणामों को दर्शाता है।
2. **लक्षित कल्याण पर ध्यान:**
    1. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) जैसी योजनाओं में बढ़े हुए वित्त पोषण का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे में सुधार करना है।
    2. NEP 2020 अधिक बजटीय सहायता पर जोर देता है, परंतु ग्रामीण-शहरी शिक्षा में अंतर फिर भी बना हुआ है।
3. **सार्वजनिक वित्त पोषण में चुनौतियाँ:**
    1. **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** ग्रामीण संस्थानों में संकाय और अनुसंधान सुविधाओं की कमी है।
    2. **असमान पहुँच**: बढ़ती छात्रवृत्ति के बावजूद भी हाशिए पर रह रहे समूहों को अभी भी अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
    3. **निधियों का अपर्याप्त उपयोग:** विलंबित कार्यान्वयन आवंटित बजट के प्रभाव को कम करता है।

उच्च शिक्षा के वित्तपोषण में असमानताओं को पाटने हेतु, राज्यों को शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का न्यूनतम 6% आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए, जैसा कि NEP 2020 द्वारा भी अनुशंसित किया गया है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का विस्तार निवेश को आकर्षित कर सकता है एवं साथ ही बुनियादी ढाँचे और अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ा सकता है। निधि के लीकेज को कम करने और आवंटित बजट के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए शासन और जवाबदेही को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, बेहतर ई-लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, खासकर वंचित क्षेत्रों में समावेशी डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने से डिजिटल डिवाइड को पाटने में मदद मिल सकती है। एक बेहतर एवं संतुलित वित्तपोषण संबंधी रणनीति न केवल समान पहुँच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करेगी बल्कि एक कुशल कार्यबल को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास में भी योगदान देगी।